

भारत में जेल सुधार की आवश्यकता : कैदियों के
मानवाधिकार के विशेष संदर्भ में



सत्र 2020-21

लघुशोध प्रबंध

मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर) की
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निदेशक

श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहायक प्राध्यापक-विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

रायकर्ता

बिमला राजवाड़े
एल.एल.एम. (चतुर्थ सेमेस्टर)
रोल नं. 1902012
नामांकन क्र. SUP18R1495
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

अनुसंधान केन्द्र

विधि विभाग राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विमला राजवाड़े पति श्री देवा राम राजवाड़े लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय भारत में जेल सुधार की आवश्यकता : कैदियों के मानवाधिकार के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया है।

इन्होंने यह लघु शोध कार्य मेरे निर्देशन व मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध इनके स्वयं के द्वारा एकत्रित किये गये तथ्यों पर आधारित है।

दिनांक - 19/12/20

स्थान - अम्बिकापुर

निर्देशक

श्री माधवरेन्द्र तिवारी

(सहायक प्राध्यापक-विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अम्बिकापुर,

जिला-सरगुजा (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय -1

01-31

प्रस्तावना

- 1.1. उपकल्पना
- 1.2. शोध की प्रविधि
- 1.3. दण्ड व्यवस्था में जेलों की भूमिका
- 1.4. अपराध निवारण में जेलों की भूमिका
- 1.5. अपराध निवारण में जेलों की अन्य भूमिका

अध्याय -2

32-45

जेल व्यवस्था का इतिहास

- 2.1 स्वतंत्रता से पूर्व जेल व्यवस्था
- 2.2 स्वतंत्रता के बाद जेल व्यवस्था
- 2.3 वैश्विक स्तर पर जेल व्यवस्था
- 2.4 भारत में जेल व्यवस्था

जेलों में कैदियों को प्राप्त अधिकार

- 3.1 संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की घोषणा पत्र में कैदियों को प्राप्त अधिकार
- 3.2 सिविल व राजनीतिक अधिकार
- 3.3 भारत के अन्य विधियों में कैदियों को प्राप्त मानवाधिकार महिला कैदियों के मानवाधिकार

भारत में जेल सुधार की आवश्यकता

- 4.1 भारतीय जेलों की समस्याएँ
- 4.2 भारत में जेल सुधार की चुनौतियाँ
- 4.3 भारत में जेल सुधार हेतु प्रयास

निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ ग्रन्थ सूची

“मीडिया की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार – एक विधिक अध्ययन”

A DESSERTATION

Submitted in partial fulfillment of the requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF



MASTER OF LAWS
IN
DEPARTMENT OF LAW

Under supervision of :

DR. MILENDRA SHINGH
Assistant Professor
DEPARTMENT OF LAW
R.G.P.G. COLLEGE AMBIKAPUR

Submitted to :

MISS PREETI YADAV
LL.M. Scholar
Roll No. - 2902301
Enrollment No.- CP/13/292

Session : 2020 – 2021

*Valued
17/12/2022*

DEPARTMENT OF LAW
R.G.P.G. COLLEGE AMBIKAPUR, SARGUJA (C.G.)

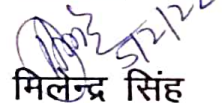
प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय "मीडिया की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार एक विधिक अध्ययन" छात्र का एक मौलिक कार्य है और राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि विभाग के एलएल.एम चतुर्थ सेमेस्टर में प्रस्तुत किया जा रहा है ।?

दिनांक –

स्थान – अम्बिकापुर (छ0ग0)

निर्देशक



श्री मिलेन्द्र सिंह

(सहा0 प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)

अनुक्रमाणिका का विवरण

अध्याय	अध्याय का विवरण
1. प्रस्तावना	1.1 परिचय
	1.2 विषय के बारे में
	1.2.1 गोपनीयता क्या है
	1.2.2 जब कोई व्यक्ति समुदायिक स्थान पर होता है तो गोपनीयता भंग नहीं होती
	1.2.3 आदर्श गोपनीयता का संबंध पूर्ण एकांत से है
	1.3 अध्ययन के उद्देश्य
	1.4 अनुसंधान का महत्व
	1.4.1 मीडिया की स्वतंत्रता गोपनीयता के अध्ययन का महत्व
	1.4.2 मीडिया का महत्व
	1.5 परिकल्पना
	1.6 शोध पद्धति
	1.7 साहित्य समीक्षा
	2. मीडिया की स्वतंत्रता और
2.2 मीडिया की अवधारणा	
2.3 मीडिया का अर्थ एवं परिभाषा	
2.4 मीडिया की स्वतंत्रता का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	
2.2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका	
2.2.2 रूस	

निजात के अधिकार की अवधारणा अर्थ एवं परिभाषा , ऐतिहासिक परिचय	2.2.3 यूरोप
	2.2.4 यूनाईटेड किंगडम
	2.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में मीडिया का इतिहास
	2.3.1 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इतिहास
	2.3.2 दिवस (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे)
	2.3.4 क्यों विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है ।
	2.3.5 विश्व में प्रेस स्वतंत्रता की भारतीय स्थिति
	2.3.6 भारत की प्रेस काउंसिल से सुरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता
	2.4 गोपनीयता का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
	2.4.1 भारत में गोपनीयता का इतिहास
	2.4.2 गोपनीयता का अधिकार की अवधारणा
	2.4.3 गोपनीयता का अर्थ और इसकी परिभाषा
	2.4.4 गोपनीयता के विभिन्न आयाम
	2.4.5 राजनीतिक गोपनीयता
	2.4.6 चिकित्सा गोपनीयता
	2.4.7 अनुवांशिक गोपनीयता
	2.4.8 इंटरनेट गोपनीयता
	3.
3.1.1 प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय आयाम	
3.1.2 संयुक्त राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता	

	3.1.3 ब्रिटेन में प्रेस की स्वतंत्रता
--	---------------------------------------

<p>प्रेस की स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य</p>	3.1.4	प्रेस स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी यूरोप में खराब ब्रिटेन
	3.2	गोपनीयता के अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय आयाम
	3.2.1	गोपनीयता का ऐतिहासिक विकास अमेरिकी राज्य
	3.2.2	मानवाधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा – 1948
	3.2.3	सिविल एवं राजनीति अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा –1966
	3.2.4	यूरोपीय अभिसमय 1960
	3.2.5	मानवाधिकारों का अमेरिकी अभिसमय – 1969
	3.2.6	संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार का विकास
	3.3	ब्रिटेन में गोपनीयता का अधिकार
<p>4. प्रेस की स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार भारतीय परिप्रेक्ष्य</p>	4.0	सामान्य
	4.1	प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय परिवेश
	4.1.1	यूनिको 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र से शुरुवात
	4.2	भारत में प्रेस की स्वतंत्रता
	4.2.1	सूचना का अधिकार कानून
	4.2.2	भारत में मीडिया परीक्षणों की संवैधानिक
	4.2.3	भारत में प्रसारण
	4.2.4	भारत में प्रसारण विधि
	4.2.5	केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन)
	4.2.6	सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952
	4.2.7	भारत में रेडियो प्रसारण
	4.2.8	मीडिया पर कोर्ट का नियंत्रण
	4.3	प्रेस की स्वतंत्रता
	4.3.1	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

	4.4 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केस स्टडी
	4.5 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए आयाम
	4.5.1 टेलीफोन टैपिंग
	4.5.2 सूचना का अधिकार
	4.6 प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध
	4.8 भारत में गोपनीयता की स्वतंत्रता
	4.8.1 क्या है ? गोपनीयता का अधिकार ?
	4.8.2 गोपनीयता की बहस
	4.9 मौलिक अनुच्छेद का निलंबन
5. न्यायिक दृष्टिकोण	5.1 सामान्य
	5.2 प्रेस की स्वतंत्रता
	5.3 प्रेस की स्वतंत्रता में न्यायपालिका की भूमिका
	5.4 लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता
	5.5 निजता का अधिकार
	5.6 निजता का अधिकार (पक्ष में दी गई दलील)
6. निष्कर्ष, सुझाव एवं परिकल्पना	6.1 निष्कर्ष
	6.2 सुझाव
	6.3 परिकल्पना का परीक्षण
7. ग्रन्थसूची	संदर्भ सूची
	वेब सूची

भारत में लैंगिक असमानता : समाजिक एवं विधिक
अध्ययन

A DISSERTATION

Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF



MASTER OF LAWS
IN
DEPARTMENT OF LAW

Under Supervision of :

Submitted By:

Mr. Brajesh Kumar

Sapna Soni

Assistant Professor

LL.M. 4th semester

Department of Law

Roll No.2902303

Govt.R.G.P.G. College

Enro. No.-AN-12/2046

Session 2020-2021

DEPARTMENT OF LAW

R.G.P.G.Govt College Ambikapur

Affiliated By:- SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALYA, AMBIKAPUR (C.G


Pin.code -497001

Valued
for
7/2/2022

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सपना सोनी ने शोध - के विषय पर शोध प्रबंध भारत में लैंगिक असमानता : समाजिक एवं विधिक अध्ययन मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध-प्रबंध सपना सोनी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) को अग्रेषित किया जाता है।

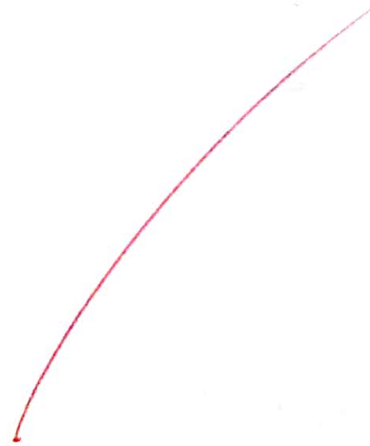
दिनांक -


श्री बूजेश कुमार

स्थान - अम्बिकापुर (छ.ग.)

(विभागाध्यक्ष विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)



अध्याय – 1 प्रस्तावना

1:1 प्रस्तावना

1-8

1:2 शोध समस्या का चयन एवं शोध प्रश्न का निर्धारण

1:3 साहित्य का पुनरावलोकन

1:4 शोध का उद्देश्य

1:5 परिकल्पना

1:6 शोध पद्धति

1:7 शोध की कार्यावधि

1:8 शोध की उपयोगिता

1:9 शोध का परिणाम

अध्याय – 2 लैंगिक असमानता का अर्थ, परिभाषा एवं समानता के उपयोगिता व महत्व

2:1 लैंगिक असमानता का अर्थ

9-28

2:2 लैंगिक असमानता का परिभाषा

2:3 लैंगिक असमानता की अवधारणा

2:4 समानता की उपयोगिता

2:5 लैंगिक समानता का महत्व

अध्याय – 3- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता

3:1 प्राचीन युग में महिलाओं का स्थान

29-64

3:2 मध्य कालीन महिलाओं की स्थिति

3:3 आधुनिक युग में महिलाएं की स्थिति

अध्याय 4 – भारतीय संविधान एवं अन्य विधियों के अन्तर्गत लैंगिक समानता

- 4:1 भारतीय संविधान में महिलाओं से सम्बंधित उपबंध 65–79
- 4:2 विधवा पूर्णविवाह अधि. 1956
- 4:3 शारदा अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध 1980
- 4:4 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955
- 4:5 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961
- 4:6 घरेलु हिंसा रोकथाम अधि 2005
- 4:7 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2005
- 4:8 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना व कार्य।

अध्याय –5– भारत में लैंगिक असमानता पर न्यायिक दृष्टिकोण

- 5:1 लैंगिक असमानता को रोकने हेतु न्यायालय के न्यायिक निर्णय 80–95
- 5:2 लिंग असमानता के प्रति जागरूकता के निर्देश

अध्याय – 6 लैंगिक असमानता अध्ययन के निष्कर्ष एवं सुझाव

- 6:1 लैंगिक असमानता अध्ययन के निष्कर्ष 96–103
- 6:2 लैंगिक असमानता में सुधार हेतु सुझाव

भारत में न्यायिक सक्रियता का विश्लेषणात्मक अध्ययन;
पर्यावरण संरक्षण के विशेष सन्दर्भ में

सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

मिनाक्षी यादव
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
रोल न. 2902298
नामांकन क्रमांक - A-10/687

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valued
17/2/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मिनाक्षी यादव , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य "भारत में न्यायिक सक्रियता का विश्लेषणात्मक अध्ययन ;पर्यावरण संरक्षण के विशेष सन्दर्भ में " कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनांक

5/2/22

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-18
1.1	विषय परिचय	2-3
1.2	शोध परिकल्पना	3
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	3-15
1.4	शोध पद्धति	15-16
1.5	तथ्य विश्लेषण प्रविधि	16
1.6	शोध के उद्देश्य एवं औचित्य	17
1.7	शोध की उपयोगिता	17
1.8	शोध की रूपरेखा	17-18
2	न्यायिक सक्रियता का अर्थ ,परिभाषा एवं विकास	19-49
2.1	न्यायिक सक्रियता की अवधारणा	20
2.2	न्याय का परम्परावादी दृष्टिकोण	20-22
2.3	भारत में जनहित मामलो का प्रारम्भ	22-27
2.4	जनहित मामलो का विकास	27-31
2.5	भारत में जनहित मामलो का विकास	31-33
2.6	न्यायिक सक्रियता	33-34

2.7	न्यायिक सक्रियता का अर्थ	35-36
2.8	न्यायिक सक्रियता का दौर	36-37
2.9	भारत में न्यायिक सक्रियता का सूत्रपात	37-39
2.10	सुनवाई के अधिकार का विस्तार एवं न्यायिक सक्रियता	39-41
2.11	न्यायिक प्रक्रिया की बदलती भूमिका	41-49
3	भारत में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान	50
3.1	सामान्य परिचय	51-55
3.2	पर्यावरण और परितंत्र	55-56
3.3	पर्यावरणीय समस्यायें	56
3.4	संसाधन न्यूनीकरण	56—57
3.5	पर्यावरणीय प्रदूषण	57
3.6	जलवायु परिवर्तन	58
3.7	जैव विविधता हास	58
3.8	प्राकृतिक आपदाये	58-59
3.9	पर्यावरण संरक्षण	59
3.10	पर्यावरण संरक्षण की समस्या	59
3.11	पर्यावरण संरक्षण का महत्व	60
3.12	पर्यावरण संरक्षण के उपाय	60-62

3.13	स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियां एवं कानून	62-63
3.14	एतिहासिक पृष्ठभूमि	63-77
3.15	पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए मानवकृत महत्वपूर्ण उपाये	77-80
4	भारत में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विधियाँ	81-94
5	पर्यावरण संरक्षण सम्बन्ध में न्यायपालिका की भूमिका	95-115
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	116-121
संदर्भ ग्रन्थ सूची		122-124

भारत में बालकों का विधिक एवं संवैधानिक
अधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन



सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध

मास्टर ऑफ लॉ (एल एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक

श्री ब्रजेश कुमार

सहायक प्राध्यापक

(विधि विभाग)

राजीव गांधी शास.स्ना.महा.वि.

अम्बिकापुर (छ.ग.)

शोधकर्ता

दीपक विश्वकर्मा

एल एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर

रोल नम्बर - 2902293

नामांकन क्र.-SUP16R1014

©2021 Deepak Vishwakarma. All Rights Reserved

अनुसंधान केन्द्र
विधि विभाग

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्त महाविद्यालय अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)


Valued
for
7/2/2022

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दीपक विश्वकर्मा लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय “भारत में बालकों का विधिक एवं संवैधानिक अधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन” मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है। यह लघु शोध कार्य, इनका मौलिक कार्य है।

स्थान - अम्बिकापुर

दिनांक -


लघु शोध निर्देशक
श्री ब्रजेश कुमार
सहायक प्राध्यापक
(विधि विभाग)
राजीव गांधी शास.स्नात.महा.वि.
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	प्रस्तावना	
1.1	भूमिका	01
अध्याय-2	बाल अधिकार अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
2.1	भूमिका।	08
2.2	बालक का अर्थ	09
2.3	बाल अधिकार की अवधारणा।	10
(अ).	अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में।	13
(ब).	भारत के संदर्भ में।	14
2.4	बाल अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।	15
(अ).	अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में	16
(ब).	भारत के संदर्भ में	17
अध्याय-3	अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बालकों के अधिकार : एक समीक्षा	
	भूमिका	19
अध्याय-4	भारतीय संविधान में बालकों के अधिकार	
4.1	भूमिका	35
4.2	भारतीय संविधान में बाल अधिकार से संबंधित उपबंध	36
(अ).	मौलिक अधिकार के अन्तर्गत बालकों के अधिकार	36
(ब).	राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत	45

बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के
विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

प्रभावती प्रभाकर
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
रोल न. 2902300
नामांकन क्रमांक - A-11/7782

Valyuel
12/12/22
अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावती प्रभाकर , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य "बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन)अधिनियम 1986 के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन "इनकी कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-8
1.1	विषय परिचय	2-3
1.2	साहित्य का पुनरवलोकन	3-4
1.3	अध्ययन का उद्देश्य	5-6
1.4	परिकल्पना	6
1.5	शोध पद्धति	6-7
1.6	शोध कार्य विधि	7
1.7	शोध की उपयोगिता	7
1.8	रूपरेखा	8
2	बालश्रम का अर्थ , अवधारणा एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण	9-39
2.1	विषय परिचय	10-13
2.2	बालश्रम की अवधारणा	13-14
2.3	बाल मजदूरी के कारण	15
2.4	बाल मजदूरी और औपचारिक स्कूली शिक्षा	15-17
2.5	एम.वी.एफ मॉडल	17-19

2.6	बाल उत्पीड़न	19-20
2.7	बाल श्रमिकों पर अत्याचार	20-25
2.8	बाल उत्पीड़न के दुष्प्रभाव	25-26
2.9	विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का वितरण	26-28
2.10	बाल श्रमिकों की कार्यदशा एवं समस्याएँ	28-30
2.11	बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रयास	30-31
2.12	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल नीति	31-33
2.13	बालश्रम के प्रभाव	33-34
2.14	एतिहासिक पृष्ठभूमि	35-38
2.15	वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बालश्रम	38-39
3	बालश्रम संरक्षण हेतु उपलब्ध विधियाँ :राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय	40-56
4	बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बालश्रम समस्या एक दृष्टिकोण	57-76
5	भारत में बालश्रम एक न्यायिक दृष्टिकोण	77-87
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	88-97
संदर्भ ग्रन्थ सूची		98-100

मानवधिकार एवं निजता का अधिकार एक विधिक अध्ययन

सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

वर्षा सोनी
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
रोल न. 2902306
नामांकन क्रमांक - A-13/3328

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valued
7/2/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्षा सोनी , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य "मानवधिकार एवं निजता का अधिकार एक विधिक अध्ययन "इनकी कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनांक

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-11
1.1	विषय परिचय	2-4
1.2	साहित्य का पुनरवलोकन	4-6
1.3	अध्ययन का उद्देश्य	6-8
1.4	परिकल्पना	8-9
1.5	शोध पद्धति	9
1.6	शोध कार्य विधि	9-10
1.7	शोध की उपयोगिता	10
1.8	रूपरेखा	10-11
2	मानवाधिकार का अर्थ ,अवधारणा एवं एतिहासिक पृष्ठभूमि	12-33
2.1	मानवाधिकार का अर्थ	13
2.2	राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस	14-15
2.3	मानवाधिकार की अवधारणा व विकास	15-19
2.4	स्वतंत्रता के घोषणा पत्र	19
2.5	हैवियस कारपस अधिनियम	19-20

2.6	मानवाधिकार का सार्वभौमिकरण	20-21
2.7	नागरिक और राजनैतिक अधिकार	21-22
2.8	मानवाधिकार के संरक्षण में न्यायविदों की भूमिका	22-23
2.9	मानव अधिकार : अभिप्राय	23-24
2.10	मानवाधिकारों का प्रादुर्भाव	25
2.11	वैश्विक परिप्रेम्य में मानवाधिकारों की उत्पत्ति	25-26
2.12	मानवाधिकार एवं विधि शासन	26
2.13	न्यायिक पुनरवलोकन एवं मानवाधिकार	27
2.14	मानव अधिकार एवं जनहित	27-28
2.15	अमानवीय कृत्य एवं मानवाधिकार	28-29
2.16	सार्वभौम घोषणा एवं मानवाधिकार	29-31
2.17	भारतीय संविधान में मूलाधिकार एवं मानवाधिकारों का संरक्षण	31-33
3	निजता का अधिकार -अर्थ ,अवधारणा एवं विकास	34-56
4	मानवाधिकार से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विधियाँ	57-75
5	निजता के अधिकार से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विधियाँ	76-84
6	मानवाधिकार एवं निजता के अधिकार से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टिकोण	85-94
7	निष्कर्ष एवं सुझाव	95-101
संदर्भ ग्रन्थ सूची		102-105

भारत में पर्यावरण संरक्षण एक विधिक अध्ययन ;
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विशेष सन्दर्भ में

सत्र 2020-21
लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

मृत्युंजय कुमार पटेल

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक - SUP16R1043

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valued
7/2/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मृत्युंजय कुमार पटेल , एल एल एम (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध "भारत में पर्यावरण संरक्षण एक विधिक अध्ययन : उच्चतम न्यायलय के निर्णयों के विशेष सन्दर्भ में "इनकी कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बद्ध राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर
दिनांक

शोध निर्देशक :
श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-23
1.1	विषय परिचय	2-4
1.2	शोध परिकल्पना	5
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	5-21
1.4	शोध पद्धति	21-22
1.5	तथ्य विश्लेषण प्रविधि	22
1.6	शोध के उद्देश्य एवं औचित्य	22-23
1.7	शोध की रूपरेखा	24
2	पर्यावरण की अवधारणा एवं विकास	24-59
2.1	सामान्य परिचय	25-28
2.2	भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चिंतन	28
2.3	पर्यावरण संरक्षण	28
2.4	पर्यावरणीय समस्याएँ	29-31
2.5	पर्यावरण संरक्षण की समस्या	31-32
2.6	पर्यावरण संरक्षण का महत्व	32
2.7	पर्यावरण संरक्षण के उपाय	32-35
2.8	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	35-52
2.9	पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए मानवकृत महत्वपूर्ण उपाय	52-55
2.10	पर्यावरण संरक्षण के अन्य उपाय	56-59

3	विशिष्ट विधियों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान	60-77
3.1	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम ,1974 तथा 1977	61-63
3.2	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम ,1981	63-65
3.3	वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम,1972	65-67
3.4	वन संरक्षण अधिनियम ,1980	67-68
3.5	ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कानून	68-69
3.6	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	69-70
3.7	जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ,2002	71-72
3.8	राष्ट्रीय जलनीति , 2002	72-73
3.9	राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ,2004	73-75
3.10	वन अधिकार अधिनियम ,2006	75-77
4	भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान	78-110
5	पर्यावरण संरक्षण में उच्चतम न्यायालय की भूमिका	111-125
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	126-128
संदर्भ ग्रन्थ सूची		129-132

MEDICAL NEGLIGENCE IN INDIA: AN ANALYTICAL STUDY



**DISSERTATION
SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF**

Master of Laws

Session 2020-2021

Under Supervision OF

MR.MADHVENDRA TIWARI
Assistant Professor
Department of Law
R.G.P.G College Ambikapur

SUBMITTED BY :

MR.VISHAL SONI
L.L.M IV Semester
Roll No. 2902313
Enrollment No.C-12/316

*Valued
for
17/2/2022*

Department of Law

Rajeev Gandhi Gov. Post Graduate College Ambikapur(c.g)

Affiliated By:-SANT GAHIRA GURRU UNIVERSITY

AMBIKAPUR , Dist:-Sarguja (C.G)



CERTIFICATE OF THE GUIDE

CERTIFIED that the work incorporated in the thesis titled **Medical Negligence in India: An Analytical Study** submitted by **Mr. VISHAL SONI** was carried out by the candidate under my supervision and guidance. Such material has been obtained from other sources has been duly acknowledged in the thesis.

Place: Ambikapur (c.g)

Date: 4/02/2022


(Mr. MADHVENDRA TIWARI)

Research Guide

CONTENTS

SR. NO	CHAPTER DESCRIPTION	PAGE NO
	Chapter I Introduction	1-14
1.1	Introduction	1
1.2	Statement of the Research Problem	3
1.3	Hypothesis	5
1.4.	Aim and Objective of Study	5
1.5.	Rational and Signification of study	6
1.6.	Scope and Limitation of study	7
1.7.	Research Methodology	8
1.8.	Review of Literature	8
1.9.	Scheme of Chapterisation	12
	Chapter II Medical Negligence: Conceptual Analysis and Historical Development	15-39
2.1	Introduction	15
2.2	Medical Negligence: Conceptual Analysis	15
	2.2.1. Negligence: Meaning and Definition	15
	2.2.2. Definition of Profession, Medical Profession and Professional Negligence	16
	2.2.3. Right to Health Care and Medical Negligence: An Interlink	17
	2.2.4. Medical Negligence: Definition	18
	2.2.5. Medical Malpractice and Medical Negligence: Differential Approach	19
	2.2.6. Kinds of Negligence	19
	1. Gross Negligence	20
	2. Comparative Negligence	20

	3. Contributory Negligence	20
	4. Composite Negligence	21
	5. Corporate Negligence	21
2.3	Medical Negligence and Nature of Its Punishment: Historical Evaluation	22
	2.3.1. During ancient and medieval period	22
	2.3.2. During pre-constitutional period	28
	2.3.3. During post-constitutional period	30
	2.3.3.1. Constitutional provision	31
	2.3.3.2. Other legal avenues	38
2.4.	Conclusion and Appraisal	39
	Chapter III Law related to medical Negligence in India and world	40-84
3.1.	Introduction	40
3.2.	Medical Negligence in UK	40
	3.2.1. Elements of Negligence:	41
	1. Duty of care	42
	2. Breach of duty	43
	3. Causation	44
	3.2.2 Medical Negligence : Regulating Principles	45
	1. National Health Service is-a- vis Private Medical Practitioners :	45
	2. NHS Litigation Authority	45
	3. Indemnity Through Medical Defense Organizations	46
	4. Clinical Negligence Program for Trusts	46
	5. Vicarious Liability of hospitals and doctors	46
	3.2.3. Clinical negligence and legal procedure:	47
	1. Clinical records	47
	2. Limitation period:	48

	3. Legal aid	48
	4. Costs	49
	5. Conditional Fee Agreement	49
	6. The Burden of Proof	49
	7. The But For Test:	50
	8. Damage	53
	9. Health Service Commissioner (the Ombudsman)	54
	3.2.4. Informed Consent and Medical Negligence:	54
	3.2.5. Judicial Interpretation	58
3.3.	Medical Malpractice in United States.	61
	3.3.1. Legal Elements of medical negligence:	61
	3.3.2. Law applicable to Medical Negligence.	64
	3.3.2.1. State Legislatures:	65
	3.3.2.2. Good Samaritan laws:	65
	3.3.2.3. Pre-Trial Screening of Cases	67
	3.3.2.4. Alternative Dispute Resolution	67
	3.3.2.5. Statutes of Limitations:	67
	3.3.2.6. Role of Expert Witnesses	68
	3.3.3. Compensation:	69
	3.3.3.1.1. Limits on Damages	69
	3.3.3.2. Attorney Compensation	71
	3.3.3.3. Joint and Several Liability	73
	3.3.3.4. Lump Sum or Periodic Payments	74
	3.3.3.5. Recoveries from Collateral Sources	74
	3.3.3.6. Patient Compensation Funds	75
	3.3.3.7 Enterprise Liability	75
	3.3.4. Aligning Malpractice Law and Patient Safety Concerns	76
	3.3.5. Role of consent	78
3.4.	Legal system pertaining to medical negligence in India, UK and USA: Comparative analysis	81

3.5.	Conclusion and appraisal:	84
	Chapter IV REDRESSAL MECHANISM UNDER CONSUMER PROTECTION ACT: A CRITICAL APPRAISAL	85-133
4.1.	Introduction	85
4.2.	Redressal Mechanism	85
	4.2.1. Remedies under Constitution of India	86
	4.2.2. Enforcement Machinery under Civil Law	87
	4.2.3. Enforcement Machinery under Criminal Law	88
	4.2.4. Medical Negligence and Medical Council of India Act: Role of Medical Council of India	89
	4.2.5. Consumer Dispute Redressal Mechanism: Three Tire System	92
	4.2.5.1. District Forum	93
	4.2.5.2. State Commission	99
	4.2.5.3. National Commission	102
4.3.	Burden of Proof and Causation	113
	4.3.1. Causation	104
	4.3.2. Res Ipsa Loquitur	107
	4.3.3. Evidence	110
4.4.	Compensation	113
4.5.	Defence against Medical Negligence	117
	1. 'But for' Test	117
	2. Locality Rule	118
	3. Error of Judgment	118
	4. Difference of Medical Opinion	120
	5. Contributory Negligence	120
	6. General Exceptions under Indian Penal Code	120
	7. Actio Personalis Moritur Cum Person	122
	8. Due Care Taken	123
	9. Rarest of Rare Cases	124
	10. Knowledge not available at the time of incident	124
	11. Period of Limitation	124
4.6.	Doctor- Patient Relationship	125
	4.6.1. Rights of Patient	125

	4.6.2. Responsibilities of a Patient	128
4.7.	Customary Mechanism and Mechanism under Consumer Protection Act: Comparative Analysis	131
4.8.	Conclusion and Appraisal	132
	CHAPTER V INTERPRETATION OF LAWS RELATING TO MEDICAL NEGLIGENCE IN INDIA- JUDICIAL ACTIVISM	134-176
5.1.	Introduction	134
5.2.	Potential areas of medical negligence cases	134
5.3.	Landmark Supreme Court Judgments on Medical Negligence	146
	5.3.1 Criminal medical cases under Indian Penal Code	147
	Chapter VIII Conclusion and Suggestions	177-194

**RAJEEV GANDHI GOVERNMENT PG
COLLEGE AMBIKAPUR(C.G.)**



**STATUS OF EXTRA JUDICIAL
KILLINGS IN SPECIAL ASPECT OF
HUMAN RIGHTS IN INDIA**

**DISSERTATION SUBMITTED FOR THE PARTIAL
FULFILLMENT OF LL.M DEGREE**

SUPERVISOR

Mr. MILENDRA SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

SUBMITTED BY

SUDHANSHU MISHRA

ROLL NO: 02139-LLM(OLD COURSE)

HUMAN RIGHTS

*Valued
7/2/2022*

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

This is to certify that the present work entitled “**Extra Judicial Killings And Human Rights In India**” is a piece of research work done by Mr Sudhanshu Mishra, under the guidance and supervision of him supervisor for the partial fulfillment of the requirement of LL.M degree of) Rajeev Gandhi PG College Ambikapur (C.G.) India. This work has been done to the subject satisfaction of him supervisor and has met with the required standards of the University.

I wish him every success in life.

Date: 20/12/2021



Mr. Milendra Singh
Assistant Professor
Supervisor

Table of Contents

DECLARATION	i
CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR	ii
ACKNOWLEDGEMENT	iii
LIST OF AUTHORITIES.....	iv
LIST OF ABBREVIATIONS.....	vi
TABLE OF CASES	viii
CHAPTER I.....	1
INTRODUCTION	2
1.1 Legality of Extra Judicial killing.....	3
1.1.1 In the context of armed conflict	3
1.1.2 Outside the context of armed conflict	4
1.1.3 The use of inter-state force.....	5
1.2 Background	6
1.3 Literature Review	10
1.3.1 Books	10
1.3.2 Articles.....	11
1.4 Statement of Problem.....	13
1.5 Hypothesis.....	13
1.6 Objectives of Study	13
1.7 Research Methodology.....	13
1.8 Limitation of Study	14
1.9 Scope of the Study.....	14
1.10 Chapterization	14
CHAPTER II.....	15
INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON EXTRA JUDICIAL KILLINGS.....	15
2.1 Sovereignty issues and States' invocation of the right to self-defence	20
2.2 The relationship between self-defence, IHL and human rights law.....	20
2.3 Anticipatory and pre-emptive self-defence	22
2.4 Extra Judicial Killings Under Various Human Rights Instruments.....	24
2.4.1 Universal Declaration of Human Rights, 1948.....	25

2.4.2 International Covenant on Civil and Political Rights, 1976.....	25
2.4.3 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984	27
2.4.4 Special Rapporteurs on summary execution and extra judicial killings.....	27
2.4.5 Model protocol for a legal investigation of extra legal, arbitrary and summary executions ("Minnesota Protocol") 2014.	32
2.4.6 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.....	34
2.5 The Widened Scope Of State Obligations And The Special Responsibility Of The State	36
2.5.1 Is there any uniform International definition for Extrajudicial killings?	39
2.6 Conclusion.....	43
CHAPTER III	47
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND HUMAN RIGHTS: INDIAN REGIME	47
CHAPTER III	48
3.1 Right of life and personal liberty.....	54
3.2 Immunity from prosecution.....	57
3.2.1 Validity of Section 197 Cr.P.C	60
3.2.2 Need for sanction when to be considered	61
3.2.3 No form of sanction but application of mind is necessary.....	61
3.2.4 Acts to fall within scope and range of official duty for availing of protection	64
3.2.5 Discretionary powers of the Governor in relation to granting sanction for the prosecution of Public Servants.....	65
3.3 Power of arrest	66
3.3.1 Pre-Arrest.....	67
3.3.2 Arrest.....	68
3.3.3 Post Arrest.....	70
3.4 Right of Private Defence	71
3.5 Abuse of Power by Public Servant.....	72
3.6 Victim's Right for Compensation	75
3.7 NHRC guidelines	81
3.8 Conclusion.....	84
CHAPTER IV	87
CASE ANALYSIS.....	87
4.1 Introduction	88

4.2 Ishrat Jahan Encounter Case	88
4.3 Batla House Encounter Case	92
4.4 Dehradun Encounter Case	98
CHAPTER V	102
CONCLUSION.....	102
BIBLIOGRAPHY	xivxiii
WEBLIOGRAPHY.....	xviii

भारत में महिला अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : घरेलू हिंसा संरक्षण
अधिनियम 2005 के विशेष संदर्भ में

सत्र 2020-21
लघु शोध प्रबंध



(एल. एल. एम चतुर्थ लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता

Kajal
काजल गुप्ता
एल.एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर
रोल नं० - 2902296
नमांकन क्रं. - A-13/3142

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा(छ0ग0)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valueed
Kajal
7/2/2022

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि काजल गुप्ता ने शोध – के विषय पर शोध प्रबंध भारत में महिला अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 के विशेष संदर्भ में मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध-प्रबंध काजल गुप्ता, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0) को अर्पित किया जाता है।

दिनांक

स्थान –अम्बिकापुर (छ0ग0)

श्री माधवेंद्र तिवारी

(सहा0 प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)

- 1.1 शोध समस्या का चयन एवं शोध प्रश्न का निर्धारण
- 1.2 साहित्य का पुनरावलोकन
- 1.3 शोध का उद्देश्य
- 1.4 परिकल्पना
- 1.5 शोध पद्धति
- 1.6 शोध की कार्यविधि
- 1.7 शोध की उपयोगिता
- 1.8 शोध का परिणाम

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं के अधिकार
- 2.3 प्राचीन भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति
- 2.4 प्राचीन भारत में महिलाओं के आर्थिक स्थिति
- 2.5 प्राचीन काल में महिलाओं की दशा
- 2.6 ऐतिहासिक प्रथाएं

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 भारतीय दण्ड संहिता 1860
- 4.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4.4 महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013
- 4.5 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994
- 4.6 अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
- 4.7 दहेज निषेध अधिनियम 1961

अध्याय-5 महिलाओं के अधिकार में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की भूमिका

- 5.1 प्रस्तावना 81-105
- 5.2 घरेलू हिंसा का अर्थ
- 5.3 भारत में घरेलू हिंसा
- 5.4 घरेलू हिंसा के कारण
- 5.5 घरेलू हिंसा के प्रकार
- 5.6 घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005
- 5.7 घरेलू हिंसा के प्रभाव

अध्याय-6 महिलाओं में घरेलू हिंसा से संरक्षण के निष्कर्ष एवं सुझाव

- 6.1 निष्कर्ष
- 6.2 महिलाओं में घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए सुझाव

**“भारत में सूचना का अधिकार : सुशासन के विशेष
संदर्भ में विधिक अध्ययन”**

A DISSERTATION

**Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF**



**MASTER OF LAWS
IN
DEPARTMENT OF LAW**

Under Supervision of :

Mr. Brajesh Kumar
Assistant Professor
Department of Law
Govt.R.G.P.G. College

Submitted By:

Binita Kachhap
LL.M. 4th semester
Roll No.2902292
Enro. No.-SUP19R0453

Session 2020-2021

DEPARTMENT OF LAW

R.G.P.G.Govt College Ambikapur

**Affiliated By:- SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALYA, AMBIKAPUR (C.G
Pin.code -497001**

Valued

7/2/2022

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि लघुशोध प्रतिवेदन जिसका विषय "भारत में सूचना का अधिकार : सुशासन के विशेष संदर्भ में विविध अध्ययन" छात्र का एक मौलिक कार्य है और राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर के विधि विभाग के एल-एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर में प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक

स्थान

बृजेश कुमार

(सहायक प्रध्यापक विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय सूची

अध्याय -1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- (1) प्रस्तावना 1-3
- (2) सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकता
- (3) सूचना के अधिकार के अन्तर्गत की व्यवस्थाएँ
- (4) उपयोगिता एवं लाभ

अध्याय -2

सूचना का अधिकार अर्थ, ऐतिहासिक विकास एवं प्रावधान

- (1) सूचना के अधिकार का अर्थ 4-13
- (2) भारत में सूचना के अधिकार का इतिहास
- (3) अधिनियम के मुख्य प्रावधान
- (4) कानून का वैश्विक अध्ययन
- (5) सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य
- (6) सूचना के अधिकार की उपलब्धियाँ
- (7) सूचना अधिनियम के हालिया संशोधन
- (8) क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार

अध्याय – 3

सुशासन का अर्थ अवधारणा एवं विकास के संबंध

- (1) सुशासन का अर्थ 14-32
- (2) सुशासन के प्रमुख तत्व
- (3) सुशासन की अवधारणा
- (4) शासन और सुशासन
- (5) सुशासन का महत्व
- (6) सुशासन विशेषताएँ
- (7) भारत में सुशासन के लिये पहल
- (8) सुशासन की राह में चुनौतियाँ
- (9) प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण

अध्याय – 4

सूचना का अधिकार का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधित स्थिति

- (1) सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय संविधिक स्थिति 33-50

- (2) सूचना के अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधिक स्थिति।
- (3) पहुंच का अधिकार : अंतर्राष्ट्रीय मानक
- (4) संयुक्त राष्ट्र
- (5) क्षेत्रीय मानक
- (6) अमेरिकी राज्यों का संगठन
- (7) एफओआई व्यवस्था की विशेषताएं
- (8) सिद्धांत 1 अधिनियम प्रकटीकरण
- (9) सिद्धांत 2 प्रकाशित करने की बाध्यता
- (10) सिद्धांत 3 खुली सरकार को बढ़ावा देना
- (11) सिद्धांत 4 अपवादों का सीमित दायरा
- (12) सिद्धांत 5 पहुंच की सुविधा के लिये प्रक्रियाएं
- (13) सिद्धांत 6 लागत
- (14) सिद्धांत 7 खुली बैठक
- (15) सिद्धांत 8 प्रकटीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।
- (16) सिद्धांत 9 संचेतक के लिए सुरक्षा

अध्याय -5

सूचना का अधिकार एवं सुशासन एक दृष्टि

(1)संदर्भ

51-65

- (2) भाग - 1 अधिकारिक गुप्तता अधिनियम व अन्य कानून
- (3) साक्ष्य मे राजकीय विशेषाधिकार
- (4) छुट प्राप्त संगठन
- (5) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम
- (6) भाग - 2 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
- (7) 1. संस्थानो का निर्माण
- (8) 2. सूचना और अभिलेख पालन
- (9) 3. निर्माण और जागरूकता सृजन
- (10) 4. क्षमता निगरानी पध्दतियों का सृजन
- (11) सूचना का आयोजन और अभिलेख पालने के संबंध मे सिफारिशें
- (12) क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के संबंध में सिफारिशें
- (13) अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालय और सार्वजनिक प्राधिकरण

अध्याय -6

सूचना का अधिकार, एवं सुशासन एवं न्यायपालिका की न्यायिक दृष्टिकोण

(1)परिचय

66-82

- (2) भारतीय न्यायपालिका प्रणाली
- (3) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- (4) सूचना का अधिकार
- (5) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की न्यायिक व्याख्या
- (6) ऐतिहासिक मामले
- (7) समाज और आरटीआई के साथ लोकतंत्र को संतुलित करना
- (8) आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट
- (9) उच्च न्यायपालिका आरटीआई के आलोक में सुशासन न्यायिक दृष्टिकोण
- (10) सुशासन
- (11) एक अच्छी सरकार की विशेषताएँ और सरकारी कार्यों की निगरानी के लिये न्यायपालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग
- (12) न्यायिक समीक्षा तीन पहलुओं के काम करती है
- (13) 1. विधारी कार्यवाही के खिलाफ न्यायिक समीक्षा
- (14) 2. न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ न्यायिक समीक्षा
- (15) 3. प्रशासनिक कार्यवाही के खिलाफ न्यायिक समीक्षा
- (16) आपातकाल की राष्ट्रपति की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा

अध्याय –7

- (1) निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत में जनसंख्या नियंत्रण में राज्य की भूमिका :
एक विधिक विश्लेषण



सत्र : 2020-21

लघु शोध प्रबंध

मास्टर ऑफ लॉ (एल एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक

शोधकर्ता

श्री माधवेन्द्र तिवारी

सहायक प्राध्यापक
विधि विभाग
राजीव गांधी शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अखिलेश कुमार पाण्डेय

एल एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक - 2902291
नामांकन क्रमांक - SUP19R0452

अनुसंधान केन्द्र

विधि विभाग

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर

जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) 497001

सम्बद्ध : संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) 497001

Value
7/2/2022

विधि विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)



प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि अखिलेश कुमार पाण्डेय, एल.एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, ने "भारत में जनसंख्या नियन्त्रण में राज्य की भूमिका : एक विधिक विश्लेषण" विषय पर लघु-शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर पूर्ण किया है।

यह इनका शोध कार्य मौलिक है। इन्होंने स्वयं लघु शोध प्रबन्ध हेतु सामग्री का संकलन कर इसका विवेचन किया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

स्थान : अम्बिकापुर

दिनांक :

निर्देशक


माधवेन्द्र तिवारी
विधि विभाग
राजीव गांधी शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा
(छत्तीसगढ़)

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रथम अध्याय : प्रस्तावना	1-13
द्वितीय अध्याय : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	14-30
तृतीय अध्याय : जनसंख्या नियन्त्रण के साधारण उपाय	31-58
चतुर्थ अध्याय : जनसंख्या नियन्त्रण में विधिक उपाय	59-95
पंचम अध्याय : न्यायिक दृष्टिकोण	96-100
षष्ठ अध्याय : निष्कर्ष एवं सुझाव	101-115
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	116-117

मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित को
प्राप्त सहायता : एक विधिक अध्ययन

सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)


लघुशोध कर्ता :

शम्भुनाथ पटेल

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक - A-13/482

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valued
7/2/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शम्भुनाथ पटेल , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध "मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित को प्राप्त सहायता : एक विधिक अध्ययन" 'इनकी कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल एम की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनांक

शोध निर्देशक :

श्री माधवेंद्र तिवारी

(सहा.प्रध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-11
1.1	प्रस्तावना	2-7
1.2	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	7-8
1.3	शोध परिकल्पना	8
1.4	साहित्य का पुनरवलोकन	9-10
1.5	शोध के उद्देश्य	9-10
1.6	शोध पद्धति	10-11
1.7	शोध की उपयोगिता	12
1.8	शोध की रूपरेखा	12-13
2	मोटर दुर्घटना के कारण एवं प्रयास	14-34
2.1	मोटर दुर्घटना से अभिप्राय	15-16
2.2	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	16
2.3	मोटर वाहन अधिनियम	17
2.4	मोटर वाहन अधिनियम के उद्देश्य	17-19
2.5	सडक दुर्घटना और भारत	19-20

2.6	दुर्घटना के कारण	20-28
2.7	दुर्घटना के प्रकार	28-31
2.8	दुर्घटनाओं की रोकथाम	31
2.9	मोटर दुर्घटना होने पर सावधानिया	31-34
3	मोटर दुर्घटना पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विधियाँ एवं दण्डात्मक प्रावधान	35-57
3.1	मोटर दुर्घटना अधिनियम ,1988	36-49
3.2	भारत में मोटर दुर्घटना	49-50
3.3	भारत में मोटर दुर्घटना स्पष्टीकरण	51
3.4	न्यायलय में पिटीशन दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	52-53
3.5	वाहन मालिक के विरुद्ध पिटीशन	54-55
3.6	पिटीशन दायर करने की तिथि	55
3.7	लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण	55-56
3.8	मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डात्मक प्रावधान	56-57
4	भारत में मोटर दुर्घटना के सम्बन्ध में पीड़ित को उपलब्ध सहायता	58-72
5	भारत में मोटर दुर्घटना पर न्यायिक दृष्टीकोण	73-80
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	81-83
7	संदर्भ सूची	84-87

भारत में श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण एवं मजदूरी
भुगतान की समस्या : एक विधिक अध्ययन

सत्र 2020-21

लघु शोध प्रबंध



(एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी

(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

सुरेखा केशरी

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

रोल न. 2902304

नामांकन क्रमांक - A-10/787

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर , सरगुजा (छ.ग.)
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

Valued
7/2/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुरेखा केशरी , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य "भारत में श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण एवं मजदूरी भुगतान की समस्या : एक विधिक अध्ययन "इनकी कृति है जिसे इन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2020-21 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनांक

शोध निर्देशक. :

श्री माधवेंद्र तिवारी 21/02/22

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-8
1.1	विषय परिचय	2-4
1.2	शोध परिकल्पना	4
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	4-5
1.4	शोध पद्धति	5-6
1.5	तथ्य विश्लेषण प्रविधि	6-7
1.6	शोध के उद्देश्य एवं औचित्य	7
1.7	शोध की उपयोगिता	7
1.8	शोध की रूपरेखा	7-8
2	श्रमिकों के संरक्षण सम्बन्धी अवधारणा एवं श्रमिक नियमन व्यवस्था	9-40
2.1	सामान्य परिचय	10-11
2.2	मजदूरी	12
2.3	मजदूरी के प्रकार	12-13
2.4	भारत में औद्योगिक मजदूरी का महत्व	13-15
2.5	औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक वर्ग का	15-17

	विकास	
2.6	पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी नीति	18-22
2.7	श्रम नीति का मूल्यांकन	22-23
2.8	श्रम नीति के दोष	23-24
2.9	मजदूरी की अवधारणायें	24-25
2.10	समयानुसार मजदूरी के दोष	25-26
2.11	कार्यानुसार मजदूरी के दोष	26-28
2.12	मजदूरी निर्धारण के तरीके	28-30
2.13	भारत में पर्याप्त मजदूरी की समस्या	30-40
3	मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान	41-73
4	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान	74-90
5	मजदूरी भुगतान की समस्या एवं न्यायालय की भूमिका	91-99
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	100-107
	संदर्भ ग्रन्थ सूची	108-110

Freedom of Religion and Religious Conversion- A Legal Study

A DESSERTATION

Submitted in partial fulfillment of the requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF



MASTER OF LAWS
IN
DEPARTMENT OF LAW

Under supervision of :

DR. MILENDRA SHINGH
Assistant Professor
DEPARTMENT OF LAW
R.G.P.G. COLLEGE AMBIKAPUR

Submitted By :

MISS DIKSHA AGRAWAL
LL.M. Scholar
Roll No. - 2902295
Enrollment No.- C-13/691

Session : 2020 – 2021

DEPARTMENT OF LAW

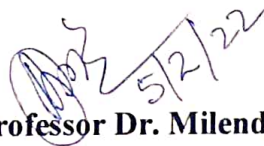
R.G.P.G. COLLEGE AMBIKAPUR, SARGUJA (C.G.)

*Valued
for
7/2/2022*

Certificate

This is to certify that Miss Diksha Agrawal has satisfactorily carried out the investigation and completed the dissertation under my guidance for the work entitled “freedom of religion and religious conversion- A legal study”. This work is being submitted for the partial fulfillment of LL.M Final semester, as per the prescribed norms of Sant Gahira Guru Sarguja University, Ambikapur. Such material as has been obtained from other sources and has been duly acknowledged in the dissertation.

Dissertation Guide

Handwritten signature and date: 5/2/22

Asst. Professor Dr. Milendra Singh

Department of Law

Rajiv Gandhi Post Graduate College, Ambikapur

Content

S.No.	Particulars	Page No.
I	Certificate	i
II	Declaration	ii
III	Acknowledgment	iii
IV	Content	iv-vi
V	Synopsis	vii-xiv
1.0	1.1 Introduction.	2
Freedom of religion and the religious conversion.	1.2 Defenitions of religion.- Taylor	2
	Durkheim	3
	Frazer	3
	Tillich	3
	Geertz	3
	Kosambi	3
	1.3 Philosophy of religion	3
	1.4 Nature and scope of religion	4
	1.5 Theories of religion- Individualist	5
	Essentalist	5
	Evolutionary	6
	Functional	6-7
	Structuralist	7-8
	1.6 World Religion	8
	1.7 Religion of India- Hinduism	8
	Buddhism	9
	Jainism	9
	Sikhism	9-10
	Islam	10
	Christanity	10
	Zoroastrianism	11
	Judaism	11
	1.8 Thinkers view on Religion-Karl marx	11
	Vivekanand ji	12
	Gandhi ji	12
	Periyar	13
	Ambedkar ji	13-14
	1.9 Religious Conversion	14
	1.10 Mass conversion	15

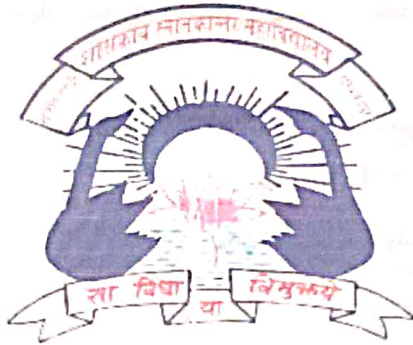
	1.11 Reconversion	16
	1.12 Anti-conversional Law	16-17
2.0	2.1 Introduction.	18
Freedom of religion under the Indian Constitution	2.2 Revolt from past on violation of freedom of religion	18-19
	2.3 Secularism and freedom of religion- Secularism	19
	2.4 Difference in concept of secularism – Secularism in India	20
	Secularism in U.S.	20
	2.5 Provisions under the Indian Constitution guaranteeing Freedom of religion. - Article 25	20-21
	Article 26	22
	Article 27	23
	Article 28	23-24
	2.6 Sabrimala Verdict and Freedom of Religion	24
	2.7 Sabrimala judgement encroached the Freedom of Religion	25
	2.8 Current position of freedom of religion.	25
3.0	3.1 Introduction	27
Religious Conversion and its impact.	3.2 Judgement of Supreme Court	27
	3.3 Enactment of Freedom of Religion Act-The Orissa Act	28
	The M.P. Dharam Swantrata Adhiniyam	29
	3.4 Pre Independence Era.	30
	3.5 Door to door religious conversion in USA	30-31
	3.6 Reasons for Conversion	31
	3.7 Libertarian Debate	31
	3.8 Communitarian Debate	32
	3.9 Right to propagate any religion	33
	3.10 Action against forceful conversion	34
	3.11 Laws for those who convert religion for wrongful gain	34
	3.12 Anti conversional laws violative of fundamental rights	35
	3.13 Legal procedure for religious conversion in India.	35
	3.14 Conversion- To Islam	36
	To Hinduisim	37
To Christianity	37	
3.15 Impact of Religious Conversion	37-38	

	3.16 Major Impacts of Conversion- Nagpur	39
	Meenakshipuram	39
	Dulina	39
	Jamait Ulma	39-40
	Delhi	40
	3.17 Aim of Indian Constitution.	40-43
4.0	4.1 Introduction	44
Constitutionality and judicial interpretation	4.2 A fundamental Right	45
	4.3 Religious conversion a human right.	45
	4.4 Case law Study	46
	4.5 Anti- conversional laws	47-51
5.0	5.1 Conclusion	52-62
Conclusion and Suggestion	5.2 Suggestion	63
V	Bibliography	64-67

**“भारत में महिला अधिकार का संरक्षण : उत्तराधिकार
कानूनों के विशेष संदर्भ में अध्ययन”**

A DISSERTATION

Submitted in partial fulfillment of the Requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF



**MASTER OF LAWS
IN
DEPARTMENT OF LAW**

Under Supervision of :

Madhyendra tiwari
Assistant Professor
Department of Law
Govt. P.G. College

Submitted By :

Rangeeta Yadav
LL.M. 4th Semester
Roll NO.- 2902312
Enroll. NO.-SUP16R1053

Session – 2020-21

DEPARTMENT OF LAW

R.G.P.G. Govt. College Ambikapur

*Valued
7/2/2022*

**Affiliated By – SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALYA,
AMBIKAPUR SURGUJA C.G. PIN CODE - 497001**

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रंगीता यादव लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय "भारत में महिला अधिकार का संरक्षण: उत्तराधिकार कानून के विशेष संदर्भ में अध्ययन " विशेष निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध – प्रबंध रंगीता यादव राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक :

स्थान: अम्बिकापुर

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
(छ0ग0)

स.क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	अध्याय – 1 भूमिका <ul style="list-style-type: none"> ● भूमिका ● साहित्य का पुनावलोकन ● शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण – ● शोध का उद्देश्य ● परिकल्पना ● शोध पद्धति ● शोध की कार्यावधि ● रूपरेखा 	1-7
2.	अध्याय – 2 महिलाओं के उत्तराधिकार के पृष्ठभूमि एवं अवधारणा <ul style="list-style-type: none"> ● उत्तराधिकार की परिभाषा ● लोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं की भागीदारी (संसद) ● भारत में महिलाओं के विरासत ● प्राचीन धर्मशास्त्र के अंतर्गत उत्तराधिकार ● सुधार लागू होने से कन्या भ्रूण-हत्या में गति आई ● लचीले सामाजिक मानदंडों की भूमिका 	8-15
3.	अध्याय – 3 भारत में हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का विश्लेषण <ul style="list-style-type: none"> ● भारत में हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ● भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार विश्लेषण महिलाओं के कानूनी अधिकार	16-43
4.	अध्याय – 4 भारत में उत्तराधिकार विधिक अधिकार विभिन्न धर्मों में <ul style="list-style-type: none"> ● भारत में उत्तराधिकार का विधिक अधिकार ● विभिन्न धर्मों में उत्तराधिकार का विधिक अधिकार 1. हिन्दू कानून	44-55

	2. मुस्लिम कानून 3. ईसाई कानून	
5.	अध्याय – 5 भारत में महिला उत्तराधिकार पर न्यायिक दृष्टिकोण <ul style="list-style-type: none">● भारतीय हिन्दू महिला अपने संपत्ति को अपने पिता के परिवार को दे सकती है (सुप्रीम कोर्ट का फैसला)● सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1 डी की व्याख्या की● संशोधन	56–66
6.	अध्याय – 6 निष्कर्ष एवं सुझाव	67–70
	संदर्भ ग्रंथ सूची	71–73

EUTHANASIA IN INDIA: A SOCIO LEGAL STUDY



A DISSERTATION

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
FOR THE AWARD OF TWO YEARS DEGREE OF**

MASTER OF LAW

IN

DEPARTMENT OF LAW

Under Supervision of:

MR. BRAJESH KUMAR

Assistant Professor

Department of Law

R.G.P.G. College Ambikapur

Submitted By:

VISHAKHA SINHA

LL.M. 4th Semester

Roll No. 2902307

Enrollment No. C-13/120

Session 2020-2021

DEPARTMENT OF LAW

Rajiv Gandhi Govt. Post Graduate College Ambikapur

Affiliated By: - SANT GAHIRA GURU VISHWAVIDYALAYA

AMBIKAPUR (C.G.), 497001

*Valued
Rs
7/2/2022*

CERTIFICATE

This is to certify that Vishakha Sinha, student of LL.M. 4th Semester, Department of Law, Session 2020-2021 from Rajiv Gandhi Govt. Post Graduate College, Ambikapur Dist Surguja, Chhattisgarh, was working under my supervision and guidance for her Dissertation Work. Her Dissertation Work entitled “EUTHANASIA IN INDIA: A SOCIO-LEGAL STUDY” which she is submitting, is genuine and original work.

Place: Ambikapur

Date:

Signature



Name: Mr. Brajesh Kumar

Supervisor

Department of Law

TABLE OF CONTENTS

<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
DECLARATION	I
CERTIFICATE	II
ACKNOWLEDGMENT	III
LIST OF CASES	IV-V
<u>CHAPTER – I</u>	
INTRODUCTION	
1.1 Introduction.....	1-3
1.2 A Brief Review of the Study.....	3-5
1.3 Objective of the Study.....	5-6
1.4 Significance of the Study.....	6-7
1.5 Research Hypothesis	7-8
1.6 Problems of the Study	8-10
1.7 Research Methodology.....	10
1.8 Chapterization.....	11
<u>CHAPTER – II</u>	
EUTHANASIA: HISTORICAL BACKGROUND	
2.1 Historical Background of Euthanasia.....	12
2.1.1 Euthanasia in Ancient Greece and Rome.....	13
2.1.2 Euthanasia in the 17 th Century.....	13-14
2.1.3 Euthanasia in the 18 th Century.....	14
2.1.4 Euthanasia in the 19 th Century.....	14

2.1.5 Euthanasia during Nazi Era.....	14-15
2.2 Background of Euthanasia in Different Religion.....	16
2.2.1 The Hindu View.....	16
2.2.2 The Buddhist View.....	17
2.2.3 The Christian View.....	17-18
2.2.4 The Muslim View.....	18-19
2.2.5 The Sikh View.....	19
2.3 Conclusion of the Chapter.....	20

CHAPTER – III

EUTHANASIA: MEANING AND CONCEPT

3.1 Meaning of Euthanasia.....	21-23
3.2 Concept of Euthanasia.....	23-25
3.3 Definitions of Euthanasia.....	25-26
3.4 Euthanasia Arises on Three Occassions.....	26-27
3.5 Reasons for Euthanasia.....	27-28
3.6 Types of Euthanasia.....	29
3.6.1 Active Euthanasia.....	29
3.6.2 Passive Euthanasia.....	29-31
3.6.3 Voluntary Euthanasia.....	31-32
3.6.4 Non-Voluntary Euthanasia.....	32
3.6.5 Involuntary Euthanasia.....	32-34
3.7 Various Perspective of Euthanasia.....	35-38
3.8 Various Disciplines Considering End-of-Issues.....	38-43
3.9 Related Concepts.....	43

3.9.1 Euthanasia and Murder.....	43-44
3.9.2 Euthanasia and Suicide.....	44-47
3.10 Conclusion of the Chapter.....	47

CHAPTER – IV

POSITION OF EUTHANASIA IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL FROM LEGAL AND SOCIAL PERSPECTIVE

4.1 Position of Euthanasia at National Level.....	48-52
4.2 Position of Euthanasia at International Level.....	53
4.2.1 Netherlands.....	53-55
4.2.2 Belgium.....	55-57
4.2.3 England.....	57-59
4.2.4 United State of America.....	59-60
4.2.5 Canada.....	60-61
4.2.6 Australia.....	61-62
4.2.7 France.....	62
4.2.8 Switzerland.....	63
4.2.9 New Zealand.....	63-64
4.2.10 Russia.....	65
4.2.11 Spain.....	65
4.2.12 Columbia.....	65
4.3 Human Rights and Euthanasia.....	66-68
4.4 Morality and Euthanasia.....	68-70
4.5 Social Perspective of Euthanasia in India.....	70-73
4.6 Conclusion of the Chapter.....	74

CHAPTER – V

JUDICIAL VIEW OF EUTHANASIA

5.1 Constitutional Perspective of Euthanasia.....	75-76
5.2 Right to Life.....	76-81
5.3 Right to Die.....	81-84
5.4 Aruna Ramchandra Shanbaug vs. Union of India: Case Analysis.....	85-87
5.5 Right to Life with Human Dignity.....	87-88
5.6 Law Commission Report on Euthanasia.....	88-92
5.7 Summary and Outcome.....	92-94

CHAPTER – VI

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

6.1 Some Arguments for Legalizing Euthanasia.....	97-101
6.2 Arguments against the Legalisation of Euthanasia.....	102-104
6.3 Critically Evaluation of the Medical Treatment of Terminally Ill Patients (Protection of Patients and Medical Practitioners) Bill, 2012.....	104-108
6.4 Conclusion.....	108-109
6.5 Suggestions.....	109-113
BIBLIOGRAPHY.....	114-118

ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN IN INDIA

- A LEGAL STUDY



**DISSERTATION
SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF**

Master of Laws

Session 2020-2021

Under Supervision OF

MR.MADHVENDRA TIWARI
Assistant Professor
Department of Law
R.G.P.G College Ambikapur

SUBMITTED BY :

MAMTA SHRIVASTAVA
L.L.M IV Semester
Roll No. 2902297
Enrollment No.C-13/329

Department of Law

Rajeev Gandhi Gov. Post Graduate College Ambikapur(c.g)

Affiliated By:-SANT GAHIRA GURRU UNIVERSITY

AMBIKAPUR , Dist:-Sarguja (C.G)

*Valued
for
17/2/2022*

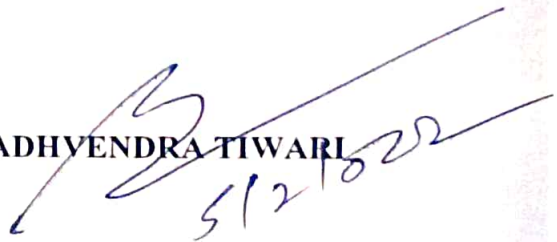
CERTIFICATE OF THE GUIDE

CERTIFIED that the work incorporated in the thesis titled "**ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN IN INDIA-A LEGAL STUDY**" submitted by Mamta Shrivastava was carried out by the candidate under my supervision guidance. Such material has been obtained from other sources has been duly acknowledged in the thesis.

Place: Ambikapur (c.g)

Date: Research Guide

MADHVENDRA TIWARI



5/2/22

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Introduction	6-11
2.	Meaning, concept and historic background of economic empowerment	12-23
	2.1 Philosopher's Views	15-16
	2.2 Women's Movements	16
	2.3 What's w-day?	16-18
	2.4 Position of Women	19
	2.4.1 In vedic period	19-20
	2.4.2 In post-vedic period	20-21
	2.4.3 Women in medieval period	21
	2.4.4 In contemporary India	21-23
3.	Economic Empowerment National and International law	
	3.0 Introduction	29
	3.1 United Nation Organization	29
	3.1.1 Time of First Phase	29
	3.1.2 In the Second Phase	30
	3.1.3 During the Third Phase	30
	3.1.4 In the existing fourth phase	30
	3.2 List of United Nation Conventions	30-32
	3.3 International Covenants on Women	32
	3.3.1 Universal Declaration on Human Rights	33-35
	3.3.2 The Convention on the Political Rights of Women, 1953	35-36
	3.3.3 Convention on the Nationality of Married Women, 1957	36-37
	3.3.4 The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966	37
	3.3.5 International Covenant on Economic, social and cultural rights, 1966	37
	3.3.6 Declaration on Elimination of Discrimination against women, 1967	37-39
	3.3.7 Convention on the elimination of all forms of discrimination against women	39-40
	3.3.7.1 Commitment of state parties	40-45
	3.4 Commission on the Status of Women	45-46
	3.4.1 State Parties were to submit the secretary	46
	3.4.2 Elimination of all forms of discrimination against women	46
	3.5 Commission of the status of women	46
	3.5.1 Vienna conference	47
	3.5.2 Beijing conference	48-55
	3.6 International law and international instrument relating the women working	55-56
	3.7 Constitutional Provisions preamble	57
	3.8 Preamble	58
	3.8.1 Political rights	58
	3.8.2 Economic Rights	59

	3.8.3 Social justice	59
	3.9 Fundamental rights	59-60
	3.9.1 Article 14	60
	3.9.2 Article 15	60
	3.9.3 Article 16	60-64
	3.9.4 Gender equality becomes illusive in absence right to leave with dignity	64
	3.9.5 Article 23	64
	3.10 Directive principles of state policy	65
	3.10.1 Article 39	65
	3.10.2 Article 39A	65
	3.10.3 Uniform civil code article 40	66
	3.10.4 Fundamental duties parts	66
	3.10.5 Article 243 D	66-68
	3.10.6 Article 243 T	68
	3.10.7 Article 243 G	69
4.	4.0 Legislative Provision	71
	4.1 Legislative Enactments	71-72
	4.2 Act 1952 The equal remuneration act 1976	72-73
	4.3 The Employees state insurance act 1948	73
	4.4 The Dowry Prohibition act	74
	4.5 "The suppression of immoral traffic act 1956"	74
	4.6 Prostitution	74
	4.7 The Sati prevention act, 1987	75
	4.8 PRE-Natal Diagnostic (Prevention) act, 1994	75-76
	4.9 Tax Benefits	76-77
	4.10 Protection of women from sexual harassment at work place	77
	4.11 Succession and maintenance	77-78
	4.12 Criminal Procedure code	78-79
	4.13 The law commission in its 84 th reports	79-80
	4.14 The hindu women's rights to property act 1937	80-81
	4.15 Hindu succession act , 1956	81-82
	4.16 The Hindu succession (Amendment)	82-84
	4.17 Equal Remuneration act, 1976	84-86
	4.18 Maternity benefit act, 1961	86-90
	4.19 The Employees State Insurance act 1948	90-96
	4.20 Mines Act	97
	4.21 The beedi and cigar workers (condition of employment) act, 1966	97-98
	4.22 National commission for women	99
	4.23 A brief history	99
	4.24 Constitution of the commission	100-101
	4.25 Legal Amendments proposed	101-103
	4.26 Complaints and counseling cell	103-104
	4.27 The national plan of action for girl child (1991-2000)	104
	4.28 Central government	105-106
	4.28.1 Women-specific legislation	107-115
	4.28.2 Legislations	116

	4.29 National policy for the empowerment of women (2001)	116
	4.30 Impact of globalization on the right of women workers	116
	4.31 Denial of basic human rights to women as a result of globalization	116-119
	4.32 Impact of globalization on women workers in India	119-120
	4.33 Human Rights of women workers need special attention	120-121
	4.34 International law and international instrument relating the women workers	121-124
5	Conclusion and suggestion	125-132